2

नर्मदापुरम: बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराई

5

राष्ट्रवाद, शिक्षा और राजनीति के पुरोधा

6

पाक अधिकृत कश्मीर में बदलाव की तस्वीर

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 11 प्रति सोमवार, 3 अगस्त 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

सामूहिक आंदोलनों ने कैसे बदले सरकारों के फैसले

लोकतंत्र की असली ताकत जनता: भारत में सामूहिक आंदोलनों की बदलती तस्वीर और उनके परिणाम

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

भारत का इतिहास केवल राजाओं, सरकारों और चुनावों का इतिहास नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों का भी इतिहास है जिन्होंने अन्याय, भ्रष्टाचार, असमानता और व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आवाज उठाई। यही आवाज कभी स्वतंत्रता संग्राम बनी, कभी संपूर्ण क्रांति, कभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, कभी निर्भया आंदोलन और कभी किसान आंदोलन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि जनता केवल वोट नहीं देती, बल्कि जब उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तब वह सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करती है। लेकिन आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां यह सवाल पहले से कहीं अधिक

तीखा होकर सामने खड़ा है। क्या भारत में आंदोलनों की राह कठिन होती जा रही है? क्या अब विरोध दर्ज कराना पहले जितना आसान नहीं रहा? क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनने का तरीका बदल गया है? या फिर बदलते समय के साथ आंदोलन भी बदल गए हैं? नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में छात्रों और अभिभावकों का व्यापक आक्रोश देखने को मिला। दिल्ली में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने यह संदेश दिया कि नई पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति पहले की तुलना में अधिक जागरूक हो चुकी है। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी। इस आंदोलन ने देशभर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर बहस को जन्म दिया और संबंधित एजेंसियों को कई स्तरों पर समीक्षा करने के लिए बाध्य किया।

(शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री साय के प्रयासों से गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान

दीनदयाल उपाध्याय योजना से गरीब परिवारों को मिली आर्थिक सुरक्षा

-विजया पाठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। इन्हीं प्रयासों के केंद्र में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है, जिसने प्रदेश के लाखों भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नया विश्वास भी जगाया है। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है, जिनकी आजीविका लंबे समय से अस्थायी रोजगार और सीमित आय पर निर्भर रही है। राज्य सरकार का मानना है कि विकास का वास्तविक लाभ तभी सार्थक है, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका प्रभाव पहुंचे। (शेष पेज 3 पर)

कमलनाथ सरकार की योजनाओं के संचालन में विफल मोहन सरकार

गौ संरक्षण में गौशालाओं का निर्माण मील का पत्थर साबित हो सकती थी लेकिन वर्तमान सरकार ने कर दिया बंटाधार

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि समय के साथ जनहित के कारण आगे भी चलती रहती हैं। यही किसी भी जननेता की दूरदृष्टि और नीति-निर्माण क्षमता का प्रमाण माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लगभग 18 माह के कार्यकाल में कई ऐसी पहलें शुरू हुईं, जिनका उद्देश्य केवल तत्कालीन राजनीतिक लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की आधारशिला रखना था। लेकिन वर्तमान सरकार कमलनाथ सरकार के विजन को आगे बढ़ाने में विफल है। सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण आमजन को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कमलनाथ की जनकल्याणकारी सोच और योजनाओं की निरंतरता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। सबसे प्रमुख योजनाओं में थी ग्राम पंचायत स्तर पर गोशालाओं के निर्माण। कमलनाथ सरकार ने गौ-संरक्षण को केवल धार्मिक या भावनात्मक विषय के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था और पशुधन संरक्षण से जोड़कर व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। (शेष पेज 3 पर)

मंत्री कश्यप के संरक्षण में चल रही राज्य में जंगलों की अंधाधुंध कटाई

विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री केदार कश्यप पर लगे ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर अवैध वसूली के आरोप

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने उन पर विभिन्न मामलों में गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब किसी मंत्री पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जाते हैं,

तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कौन से कदम आवश्यक हैं। वन विभाग के कामकाज, जंगलों के संरक्षण, भूमि आवंटन और परिवहन व्यवस्था से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। (शेष पेज 5 पर)

हावड़ा जिले में जनगणना 2027 का शुभारंभ

-अमित राय

जगत प्रवाह. हावड़ा। जिले में जनगणना 2027 का कार्य शुरू हो गया है। इस चरण में स्व-गणना, गृह सूचीकरण तथा आवास जनगणना का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाएगा। हावड़ा की जिलाधिकारी पी. दीपप्रिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि जनगणना 2027 का कार्य 'स्व-गणना' प्रक्रिया के माध्यम से 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद पूरे जिले में 16 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 7,642 गणनाकर्मी और 1,273 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वे जिले के 14 ग्रामीण विकास खंडों तथा बाली और उलुबेड़िया नगरपालिकाओं के अंतर्गत घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। यह कार्य जनगणना अधिनियम तथा भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, जनजागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। जनगणना के प्रति व्यापक जनजागरूकता पैदा करने के लिए पूरे जिले में सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) से संबंधित गतिविधियां चलाई जा रही हैं। लोगों की भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर तथा ऑडियो प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

गुरु पूर्णिमा उत्सव ने दिया भारतीय संस्कृति का प्रेरक संदेश

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नालेज पब्लिक स्कूल टिमरनी में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती निशा सिंह सिसोदिया ने अपने संबोधन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि विधार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण एवं उज्जवल भविष्य की दिशा भी निर्धारित करते हैं उन्होंने विधार्थियों से अपने गुरुजनों के प्रति सदैव सम्मान एवं कृतज्ञता का भाव बनाए रखने का आव्हान किया। इस अवसर पर विधार्थियों ने गुरु वंदना, भजन, कविता पाठ भाषण तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा का महत्व प्रस्तुत किया। विधार्थियों ने अपने शिक्षकों का तिलक, पुष्प से अभिनंदन किया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण भावपूर्ण एवं प्रेरणादायक बन गया। इसी के साथ विद्यालय के संगीत शिक्षक ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मधुर गीत प्रस्तुत किया तथा सभी शिक्षकों ने गुरूओ के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य,उप प्राचार्य, समस्त शिक्षक,शिक्षिकाए, विधार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराई

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। महिला एवं बाल विकास परियोजना शहरी के सेक्टर 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 96/98 हनुमान नगर रसूलिया में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराई गई। इस विजिट के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को श्री विद्या स्कूल में होने वाली समस्त प्रकार की गतिविधियों का अवलोकन कराया गया। अंत में बच्चों को विद्यालय के बच्चों से परिचय करा कर रंगोली, चित्रकला, खेलकूद आदि गतिविधि कराई गई। भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्योति ठाकुर, ममता बामलिया, सहायिका सुषमा विनायक, कंचन बनोध एवं स्कूल के समस्त शिक्षक उपस्थित रहे।

लोकतंत्र की असली ताकत जनता: भारत में सामूहिक आंदोलनों की बदलती तस्वीर और उनके परिणाम

यह केवल एक परीक्षा का विवाद नहीं था, यह उस भरोसे का सवाल था, जिस पर करोड़ों युवाओं का टिका हुआ था भविष्य

जब किसी छात्र का एक-एक अंक उसके जीवन का निर्णय करता हो, जब एक परीक्षा के लिए वर्षों की मेहनत दांव पर लगी हो, तब परीक्षा की निष्पक्षता केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह जाती, बल्कि यह सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक विश्वास का प्रश्न बन जाती है। यही कारण था कि इस आंदोलन ने धीरे-धीरे देश की सोच बदलनी शुरू कर दी। पहले यह चर्चा केवल परीक्षा तक सीमित थी। फिर सवाल उठा कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था सुरक्षित है? क्या पेपर लीक केवल एक घटना है या एक बड़ी समस्या का संकेत? क्या करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक हैं?

(पेज 1 का शेष)

इन सवालों का उत्तर केवल राजनीति में नहीं, बल्कि भारत के युवाओं की आंखों में दिखाई देता है। देश का युवा, जो कभी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों लगा देता है, कभी सरकारी भर्तियों के इंतजार में अपनी उम्र गुजार देता है, वह आज केवल नौकरी नहीं मांग रहा। वह निष्पक्ष व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही भी मांग रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में छात्र आंदोलन केवल कैंपस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गए। इसी पृष्ठभूमि में NEET परीक्षा को लेकर उठा आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर सामने आया। शुरुआत कुछ छात्रों की शिकायतों से हुई। फिर पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। देखते-ही-देखते यह मुद्दा लाखों छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे देश की चिंता बन गया। सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हुए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए, अदालतों में याचिकाएं दायर हुईं और संसद तक इस मुद्दे की गूंज पहुंची।

इन सवालों ने राष्ट्रीय बहस की दिशा बदल दी

सरकार ने जांच एजेंसियों को सक्रिय किया। विभिन्न स्तरों पर जांच शुरू हुई। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। परीक्षा प्रणाली में सुधारों की घोषणा की गई। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया। विपक्ष ने जवाबदेही तय करने की मांग की। अंततः शिक्षा मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। यह घटनाक्रम इस बात का संकेत बना कि शिक्षा से जुड़ा जनदबाव राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुका था। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल राजनीतिक घटनाक्रम नहीं थी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि देश के करोड़ों युवाओं ने पहली बार महसूस कराया कि उनकी आवाज केवल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। यदि वे संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें, तो पूरा देश उस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठता है। यदि आंदोलन इतना प्रभावशाली था, तो क्या इसका अर्थ यह है कि भारत में आंदोलन आसान हो गए हैं? उत्तर शायद नहीं है।

यही आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है

एक ओर संविधान नागरिकों को विरोध का अधिकार देता है, दूसरी ओर सरकार पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। इसी संतुलन के बीच हर आंदोलन अपनी राह तलाशता है। फिर भी इतिहास बार-बार यह साबित करता है कि जब कोई आंदोलन केवल नारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के बड़े वर्ग की भावना बन जाता है, तब उसे अनदेखा करना आसान नहीं होता। स्वतंत्रता आंदोलन, जेपी आंदोलन, निर्भया आंदोलन, किसान आंदोलन और हाल के छात्र आंदोलनों ने अलग-अलग समय में यही संदेश दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज अंततः राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। NEET आंदोलन ने भी एक बड़ा संदेश छोड़ा। भारत का युवा अब केवल परीक्षा देने वाला उम्मीदवार नहीं है, वह अपने अधिकारों, अपने भविष्य और व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर भी सजग नागरिक है।

यह आंदोलन चाहे इतिहास में जिस नाम से दर्ज हो, लेकिन उसने एक तथ्य स्पष्ट कर दिया। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आज भी जनता है। और जब जनता के साथ करोड़ों युवा खड़े हो जाएं, तो किसी भी मुद्दे को केवल प्रशासनिक फाइल में बंद रखना संभव नहीं रह जाता। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत है। इसने केवल एक परीक्षा पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि युवाओं का विश्वास व्यवस्था से उठ गया, तो किसी भी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता।

मध्यप्रदेश में किसानों का सामूहिक प्रदर्शन

दिल्ली के बाद सामूहिक आंदोलन की यह भावना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल तक भी पहुंची। यहां किसानों ने डीएपी और यूरिया की कमी, मूंग खरीद में सीमित कोटा तथा सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में चक्काजाम और व्यापक प्रदर्शन किए। किसानों का कहना था कि उनकी उपज की खरीद और खेती के लिए आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आंदोलन के दबाव और किसानों की एकजुटता का परिणाम यह हुआ कि मध्यप्रदेश सरकार को महज दो दिनों के भीतर किसानों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना पड़ा। सरकार ने मूंग खरीद के नियमों में संशोधन करते हुए खरीद का कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण और संगठित आंदोलन किस प्रकार नीतिगत बदलाव का कारण बन सकते हैं।

मुझे भी कई बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने का मिला मौका

मध्यप्रदेश की राजनीति में भी ऐसा एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिला। 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान सोम डिस्टिलरी को शराब दुकानों के आवंटन को लेकर व्यापक असंतोष था। उस समय इस व्यवस्था के विरोध में जनस्तर पर मजबूत आवाज उठाई गई। लगातार विरोध और आंदोलन के परिणामस्वरूप तत्कालीन सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा तथा शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि यदि किसी मुद्दे पर जनता संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराए, तो सरकारें भी अपने निर्णयों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो सकती हैं। उसके बाद नर्मदा बचाओ समिति की मेधा पाटकर के साथ मिलकर नर्मदा नदी बचाने की मुहिम में भी शामिल होने का अवसर मिला।

कमलनाथ सरकार की योजनाओं के संचालन में विफल मोहन सरकार

(पेज 1 का शेष)

सरकार की सोच थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था विकसित हो, जहां निराश्रित एवं बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सके। इससे किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और पशुधन का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। लेकिन आज पशुधन की क्या स्थिति है सबको पता है। गौशालाओं में कम सड़कों पर ज्यादा पशुधन दिख रहा है। प्रतिदिन इनकी मौतें हो रही हैं। गौशालाएं अव्यस्थित हो गई हैं।

घोषणाएं भर नहीं, सही क्रियान्वयन भी जरूरी

कमलनाथ की प्रशासनिक शैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि वे योजनाओं की घोषणा के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देते थे। अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें, समयबद्ध लक्ष्य और विकास कार्यों की निगरानी उनकी कार्यशैली की विशेषता मानी जाती थी। यही कारण था कि कम समय के कार्यकाल में भी अनेक योजनाओं की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई। मोहन सरकार उनकी योजनाओं की नकल तो कर रही है लेकिन उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नही हो रहा है।

नए नामों के साथ आगे बढ़ रही योजनाएं

कमलनाथ का दृष्टिकोण केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, उद्योग, निवेश, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक क्षेत्रों को समान प्राथमिकता देने का था। कृषि क्षेत्र में उनकी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए। किसानों को राहत देने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया। उनका मानना था कि यदि गांव मजबूत होंगे

तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। किसानों को राहत देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना भी था। आज किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो रहे हैं। किसानों को अपनी उपज का सही दाम तक नहीं मिल पा रहा है। अपनी उपज को बेचने के लिए लाईनों में लगना पड़ रहा है। मूंग खरीदी को लेकर कमलनाथ किसानों के साथ खड़े दिखाई दिये। यदि ऐसी योजनाएं आगे भी विभिन्न सरकारों द्वारा जारी रखी जाती हैं, तो यह उनकी उपयोगिता का संकेत माना जा सकता है।

कमलनाथ ने उठाए कई नीतिगत कदम

महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी कमलनाथ सरकार ने कई नीतिगत कदम उठाने का प्रयास किया। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। उनका दृष्टिकोण यह था कि विकास तभी सार्थक होगा, जब समाज का प्रत्येक वर्ग उसकी मुख्यधारा में शामिल हो।

युवाओं के लिए रोजगार के बढ़ाए कदम

युवाओं के लिए रोजगार और निवेश को लेकर भी कमलनाथ सरकार सक्रिय दिखाई दी। उद्योगों में निवेश आकर्षित करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में प्रयास किए गए। कमलनाथ का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग और वाणिज्य से जुड़ा रहा है, जिसका प्रभाव उनकी कार्यशैली में भी दिखाई देता था। उन्होंने निवेशकों का विश्वास जीतने और मध्यप्रदेश को औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण देने की दिशा में पहल की।

जनता का हित है सर्वोपरि

आज जब प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में शुरू की गई कई अवधारणाओं पर नए स्वरूप में कार्य होता दिखाई देता है, तब यह चर्चा स्वाभाविक रूप से सामने आती है कि विकास की अच्छी सोच किसी एक दल या सरकार की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की पूंजी होती है। यदि ऐसी योजनाएं निरंतर आगे बढ़ती हैं, तो अंततः लाभ जनता को ही मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 माह का कार्यकाल समय की दृष्टि से भले सीमित रहा, लेकिन उस दौरान जिस प्रकार योजनाओं की आधारशिला रखी गई, उसने प्रदेश के विकास विमर्श को नई दिशा दी। यही कारण है कि उनकी कई पहलें आज भी राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बनी रहती हैं। जनहित को केंद्र में रखकर योजनाओं की परिकल्पना करना और उन्हें दीर्घकालिक दृष्टि से तैयार करना उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है।

मुख्यमंत्री साय के प्रयासों से गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान

(पेज 1 का शेष)

इसी सोच के अनुरूप संचालित इस योजना के अंतर्गत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के माध्यम से राशि बिना किसी बिचौलिये के हितग्राहियों तक पहुंच रही है, जिससे योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता दोनों सुनिश्चित हो रही हैं।

नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है उद्देश्य

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। भूमिहीन कृषि मजदूर समाज का वह वर्ग है, जो खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन स्वयं कृषि भूमि के अभाव में आर्थिक असुरक्षा का सामना करता है। ऐसे परिवारों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत लगभग 06 लाख हितग्राही परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्रों में निवास करने वाले पात्र परिवार भी शामिल हैं। विशेष रूप से बैगा-गुनिया समुदाय सहित सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार योजनाओं का लाभ समाज के हर पात्र वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

10 हजार रुपये की वार्षिक सहायता

योजना के तहत मिलने वाली 10 हजार रुपये की वार्षिक सहायता अनेक परिवारों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो रही है। दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवार इस राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, घरेलू आवश्यकताओं और अन्य जरूरी खर्चों में कर रहे हैं। जिन परिवारों के लिए पहले नियमित आय के अभाव में भविष्य की योजना बनाना कठिन था, वे अब इस सहायता के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कई हितग्राही इस आर्थिक सहायता का एक हिस्सा बचाकर स्वरोजगार की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ परिवार पशुपालन, छोटी दुकानों, घरेलू व्यवसाय अथवा अन्य आयवर्धक गतिविधियों की शुरुआत की योजना बना रहे हैं। इससे यह योजना केवल सहायता तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरणा देने वाला माध्यम भी बन रही है।

बच्चों की पढ़ाई से स्वास्थ्य तक की सुरक्षा

सरकार के अनुसार योजना का सबसे बड़ा प्रभाव हितग्राहियों के मनोबल पर दिखाई दे रहा है। आर्थिक सहयोग मिलने से परिवारों में भविष्य को लेकर विश्वास बढ़ा है। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें समय पर पूरी हों और घरेलू खर्चों के लिए कर्ज का सहारा कम लेना पड़े इन सभी क्षेत्रों में योजना सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूर, चरवाहा, नाई, धोबी, मोची, वनोपज संग्राहक सहित अन्य निर्धारित श्रेणियों के पात्र परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यापक दायरे के कारण समाज के विभिन्न श्रमिक वर्गों को आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।

प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल

राज्य सरकार का कहना है कि योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देना भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ऐसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है, जिनसे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इसी कारण दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को प्रदेश की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। हितग्राहियों की प्रतिक्रियाएं भी योजना की उपयोगिता को दर्शाती हैं। लाभार्थियों का कहना है कि पहले उन्हें इस प्रकार की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद नहीं थी। योजना से प्राप्त राशि ने उनके परिवार की आर्थिक चिंताओं को काफी हद तक कम किया है। बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों की व्यवस्था और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में उन्हें बड़ी राहत मिली है। कई परिवारों ने इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली पहल बताया है। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं को समझते हुए ऐसी योजना लागू की है, जिससे गरीब परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। उनका कहना है कि यह आर्थिक सहयोग केवल राशि नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति विश्वास और आत्मसम्मान का आधार भी है।

ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति

विशेषज्ञों का भी मानना है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आधारित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है, तो उसका उपयोग परिवार अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार कर पाते हैं। इससे स्थानीय बाजार में भी आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति बढ़ती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदायों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ यह योजना भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने का कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे वे केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा न करें, बल्कि भविष्य के लिए भी आत्मनिर्भर बन सकें।

सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास की दिशा

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आज केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि लाखों भूमिहीन परिवारों के लिए आशा, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित यह पहल राज्य सरकार की उस सोच को भी प्रतिबिंबित करती है, जिसमें विकास का केंद्र समाज का अंतिम व्यक्ति है। आर्थिक सहायता, पारदर्शी व्यवस्था, व्यापक पात्रता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी विशेषताओं के कारण यह योजना प्रदेश के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही है और सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रही है।

सम्पादकीय

दतिया उपचुनाव: जनादेश, जवाबदेही और लोकतंत्र की नई कसौटी

मध्य प्रदेश के दतिया में संपन्न हुआ उपचुनाव केवल एक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया भर नहीं था, बल्कि यह जनता की अपेक्षाओं, राजनीतिक दलों की रणनीतियों और लोकतांत्रिक जवाबदेही की भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा रहा। उपचुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित होते हैं, किंतु उनके परिणाम राज्य की राजनीति और भविष्य की दिशा पर भी प्रभाव डालते हैं। दतिया उपचुनाव ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि मतदाता अब केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और जनहित के ठोस कार्यों के आधार पर अपना निर्णय देने लगे हैं। दतिया ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ की जनता लंबे समय से सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और शहरी सुविधाओं जैसे बुनियादी मुद्दों के समाधान की अपेक्षा करती रही है। उपचुनाव के दौरान भी इन विषयों ने राजनीतिक विमर्श में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र, चुनावी सभाओं और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से मतदाताओं का विश्वास जीतने का प्रयास किया।

भारतीय लोकतंत्र में उपचुनावों का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि वे सरकार और जनप्रतिनिधियों के कार्यों का मध्यावधि मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। मतदाता यह संदेश देते हैं कि वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से केवल चुनावी वादे नहीं, बल्कि उनके समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन की भी अपेक्षा रखते हैं। दतिया का उपचुनाव भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, जहाँ मतदाताओं ने स्थानीय समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दी। इस चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरी सक्रियता दिखाई। चुनाव प्रचार के दौरान विकास योजनाओं, किसानों की समस्याओं, युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही, मतदाताओं ने उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि, जनसंपर्क, उपलब्धता और कार्यशैली को भी अपने निर्णय का आधार बनाया। यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के परिपक्व होने का संकेत है।

लोकतंत्र की सफलता केवल मतदान प्रतिशत से नहीं, बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव से भी मापी जाती है। यदि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और कानून-व्यवस्था के बीच संपन्न होती है, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को और मजबूत करती है। दतिया उपचुनाव ने भी यह संदेश दिया कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति मतदाता के विवेक और उसकी सक्रिय भागीदारी में निहित है। उपचुनाव के परिणाम चाहे जिस दल के पक्ष में गए हों, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरता है। चुनाव जीतना किसी जनप्रतिनिधि की अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व की शुरुआत है। दतिया की जनता अब अपने प्रतिनिधि से क्षेत्र के विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, किसानों की समस्याओं के समाधान और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की अपेक्षा करेगी। राजनीतिक दलों के लिए भी यह उपचुनाव आत्ममंथन का अवसर है। चुनावी सफलता या असफलता दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जनादेश का सम्मान करते हुए दलों को संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और जनहितकारी नीतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष भी उतना ही आवश्यक है जितनी प्रभावी सरकार, क्योंकि यही व्यवस्था जनहित के मुद्दों को निरंतर जीवित रखती है। दतिया उपचुनाव का व्यापक संदेश यह है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। मतदाता अब अधिक जागरूक, सजग और उत्तरदायी हो चुका है। वह विकास, पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को प्राथमिकता देता है।

सियासी गहमागहमी

अधूरे अरमान और नई प्रशासनिक दिशा

मध्य प्रदेश में अशोक वर्णवाल के मुख्य सचिव बनने के साथ ही प्रशासनिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। इस नियुक्ति ने जहाँ शासन को नया नेतृत्व दिया, वहीं मुख्य सचिव पद की दौड़ में शामिल कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की उम्मीदें अधूरी रह गईं। प्रशासनिक सेवा में शीर्ष पद तक पहुँचना प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी की स्वाभाविक आकांक्षा होती है, लेकिन अंततः निर्णय सरकार की प्राथमिकताओं, प्रशासनिक आवश्यकताओं और नेतृत्व की कार्यशैली को ध्यान में रखकर लिया जाता है। मुख्य सचिव का पद केवल वरिष्ठता का नहीं, बल्कि अनुभव, समन्वय क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और सरकार के विज़न को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में किसी एक अधिकारी का चयन होना और अन्य दावेदारों का पीछे रह जाना प्रशासनिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि नए मुख्य सचिव शासन की प्राथमिकताओं को किस प्रकार गति देते हैं और प्रशासनिक तंत्र में किस तरह के सुधार लाते हैं। वहीं, जिन अधिकारियों की उम्मीदें इस बार पूरी नहीं हो सकीं, उनके अनुभव और क्षमता का उपयोग राज्य के अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में किया जाना भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उतना ही आवश्यक है। अंततः किसी भी नियुक्ति की वास्तविक सफलता का आकलन उसके परिणामों और जनहित में किए गए कार्यों से होता है।

आखिर किसे मिलेगी प्रदेश कांग्रेस की नई जिम्मेदारी?

मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व को लेकर एक बार फिर राजनीतिक चर्चाएँ तेज हो गई हैं। संगठन को नई दिशा देने और आगामी चुनावी चुनौतियों के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नए चेहरे की संभावनाओं को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, लेकिन यह तय है कि नए अध्यक्ष के सामने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने और विपक्ष की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने जैसी बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी। कांग्रेस के लिए यह केवल एक पद की नियुक्ति नहीं, बल्कि संगठनात्मक रणनीति तय करने का अवसर भी है। पार्टी ऐसे नेता की तलाश में होगी जो सभी गुटों के बीच संतुलन स्थापित कर सके, जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखे और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय बना सके। फिलहाल नामों को लेकर कई तरह की चर्चाएँ हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक सभी दावे केवल राजनीतिक अटकलें ही माने जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस की नई जिम्मेदारी किसे मिलती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि यह निर्णय पार्टी की भविष्य की रणनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता के आंसू, उनका बिलखना - इससे बड़ा कोई दुःख नहीं होता।
ये एक ग्राम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा - और साथ ही रह जाते हैं इस टूटी और भ्रष्ट education system के बारे में कई सवाल।
पेपर लीक | रद्द परीक्षाएं | सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद - हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

दतिया उपचुनाव में लोकतंत्र पर हमला!
आज मतदान के दौरान सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया गया।
रामसागर के पोलिंग क्रमांक 51 से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बिना कारण बताए पुलिस अपने साथ ले गई। ताकि निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो और बूथ कैप्चरिंग हो सके!
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

डॉ. मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रवाद, शिक्षा और राजनीति के पुरोधा

समता पाठक/जगत प्रवाह

डॉ. मुरली मनोहर जोशी भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेताओं, शिक्षाविदों और प्रखर विचारकों में गिने जाते हैं। वे भाजपा के प्रमुख संस्थापक नेताओं में से एक रहे हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्रहित, शिक्षा, संस्कृति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए कार्य करते रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे तथा केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। उनका व्यक्तित्व एक विद्वान, वैज्ञानिक और कुशल राजनेता के रूप में जाना जाता है। डॉ. मुरली मनोहर जोशी का जन्म 5 जनवरी 1934 को दिल्ली में हुआ। उनका पैतृक संबंध उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र से माना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। उन्होंने भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और बाद में इसी विषय में पीएच.डी. की डिग्री हासिल की। वे लंबे समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक रहे। अध्यापन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित करने का प्रयास किया।

युवा अवस्था से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और उसके वैचारिक कार्यों से जुड़े। देश और समाज की सेवा की भावना ने उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर प्रेरित किया। वर्ष 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी में विलय के बाद वे भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए और संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1991 से 1993 तक डॉ. मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन का विस्तार किया और वैचारिक रूप से स्वयं को अधिक सशक्त बनाया। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत और सुशासन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। डॉ. जोशी कई बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा बाद में कानपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। संसद में वे अपनी विद्वत्तापूर्ण, तथ्यपूर्ण और संतुलित शैली के लिए प्रसिद्ध रहे। शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक विषयों पर उनके भाषण विशेष रूप से सराहे जाते रहे हैं।

वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया। उनके कार्यकाल में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े अनेक सुधारात्मक प्रयास किए गए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रगति को गति देने का समर्थन किया। शिक्षा नीति को भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के साथ आगे बढ़ाने की उनकी सोच विशेष रूप से चर्चित रही। डॉ. मुरली मनोहर जोशी का राजनीतिक जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा रहा है। वर्ष 1991 में उन्होंने कन्याकुमारी से नगर तक "एकता यात्रा" का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देना था। इस यात्रा का समापन नगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया गया, जिसे उनके राजनीतिक जीवन की उल्लेखनीय उपलब्धियों में गिना जाता है। वे एक लेखक, चिंतक और वक्ता के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रवाद, विज्ञान और सामाजिक विषयों पर अनेक लेख लिखे तथा विभिन्न मंचों पर व्याख्यान दिए। उनका मानना रहा है कि भारत का विकास आधुनिक विज्ञान, तकनीकी प्रगति और अपनी सांस्कृतिक विरासत के संतुलित समन्वय से ही संभव है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी का सार्वजनिक जीवन सादगी, अनुशासन और वैचारिक प्रतिबद्धता का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम न मानकर राष्ट्र निर्माण का साधन माना। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े विषयों को लगातार महत्व दिया। भारतीय राजनीति में उनका योगदान एक विद्वान राजनेता, कुशल संगठनकर्ता और दूरदर्शी विचारक के रूप में स्मरणीय रहेगा। उनके कार्य और विचार आज भी अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

गदरपुर में 2,830.07 लाख की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के लिए विकास का अर्थ केवल सड़क, पुल और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल शिलान्यास तक सीमित रहने वाली सरकार नहीं है। पिछली सरकारों की तरह योजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें भुलाया नहीं जाता, बल्कि प्रत्येक परियोजना को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर उसका लोकार्पण किया जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसी कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जिसमें शिलान्यास को समयबद्ध रूप से लोकार्पण में बदलना ही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। मुख्यमंत्री

पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर बस स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में 2,830.07 लाख लागत की 08 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने गदरपुर क्षेत्र को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए 694.06 लाख लागत की पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 2,136.01 लाख लागत की नई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 275.70 लाख की लागत से निर्मित विकास खंड गदरपुर के कार्यालय भवन, 69.19 लाख की लागत से ग्रामीण क्षेत्र में हरिचंद्र-गुरुचंद्र बंग विशाल सामुदायिक भवन तथा 349.17 लाख की लागत से निर्मित गदरपुर बस अड्डे का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 1,839.70 लाख की लागत से गदरपुर में बाबा डल मंदिर से बौर जलाशय (डेस्टिनेशन) होते हुए गुलरभोज कूल्हा तिलपुरी वन बैरियर तक सिंचाई विभाग के माध्यम से कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य, 67.29 लाख की लागत से रामजीवनपुर नंबर-3 एवं ग्राम मझरशिला के आंतरिक मार्गों में इंटरलॉकिंग टाइल रोड निर्माण कार्य, 87.09 लाख की लागत से गदरपुर की जयनगर नंबर-4 कॉलोनी के विभिन्न मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल निर्माण कार्य, 57.82 लाख की लागत से गुरुनानकपुर के आंतरिक मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल निर्माण कार्य तथा 84.11 लाख की लागत से कुल्हा चौराहे से लक्ष्मण सिंह गट्टी ग्राम तक इंटरलॉकिंग टाइल रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से गदरपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के समस्त क्षेत्रों के लोगों को भी व्यापक लाभ मिलेगा और इससे पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति एवं नई पहचान प्राप्त होगी।

मंत्री कश्यप के संरक्षण में चल रही राज्य में जंगलों की अंधाधुंध कटाई

(पेज 1 का शेष)

सूत्रों के अनुसार मंत्री कश्यप ने 200 करोड़ से अधिक की अवैध वसूली महज ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से कर डाली, जिसके मुख्य सूत्रधार उनके ओएसडी रहे हैं।

पहले भी रह चुके हैं विवादों में कश्यप

हाल के दिनों में जगदलपुर सर्किट हाउस के एक संविदा रसोइये द्वारा मंत्री के साथ कथित विवाद का मामला चर्चा में रहा। इसके बाद विपक्ष ने ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर भी मंत्री और उनके कार्यालय पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्थानांतरण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

जनता को जवाब दें- मंत्री कश्यप या भाजपा

लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित कराना भी है। वहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उठाए गए प्रश्नों का तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के साथ उत्तर दे। यदि आरोप निराधार हैं तो उन्हें प्रमाण सहित खारिज किया जाना चाहिए, और यदि किसी शिकायत में प्रथमदृष्टया आधार मिलता है तो निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री के सुशासन प्रणाली को धूमिल कर रहे कश्यप

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार लगातार सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की बात करती रही है। ऐसे में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच सरकार के सामने यह अवसर भी है कि वह स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब देकर जनता का विश्वास और मजबूत करे। पारदर्शिता केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सुशासन की आधारशिला है। राज्य में औद्योगिक विकास, वन संरक्षण और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े मामलों में जनविश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए किसी भी विवाद की निष्पक्ष जांच और समयबद्ध निष्कर्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। जांच एजेंसियों और संबंधित विभागों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का संदेह समाप्त हो सके।

उद्योगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं कश्यप

मंत्री कश्यप का लालच इस हद तक बढ़ गया है कि उन्होंने राज्य के अंदर जंगलों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार हसदेव में जो जंगलों की कटाई हुई है। वह मंत्री कश्यप के आते ही और तेज हो गई है। वह चाहते तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगा सकते थे, लेकिन चूंकि उद्योग संचालित करने वाले मालिकों से इनकी दोस्ती है। इसलिए वह उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सारे काम करते हैं। इन्हें जनहित के काम से या जंगलों को नष्ट किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नए पेड़ लगाने के भी जो दावे किए जा रहे हैं। वह भी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो पेड़ काटे गए हैं वह सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, जिनकी भरपाई नए पेड़ लगाकर कभी भी नहीं हो सकती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य के वन विभाग से एक रिपोर्ट मांगी। पीईकेबी कोयला ब्लॉक 1,898 हेक्टेयर वन भूमि में फैला हुआ है। चरण 1 का खनन 762 हेक्टेयर पर पूरा हो चुका है जबकि चरण 2 शेष 1,136 हेक्टेयर पर चल रहा है। साल 2012 और 2022 के बीच खनन के पहले चरण में कुल 81,866 पेड़ काटे गए। चरण 2 के तहत 113 हेक्टेयर पर लगभग 17,460 पेड़ काटे गए हैं। पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए 53 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

पारदर्शी प्रशासनिक प्रकिया अपनाये मंत्री कश्यप

राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों से सामान्य नागरिकों की अपेक्षाएं अधिक होती हैं। इसलिए मंत्री हों या अन्य जनप्रतिनिधि, उन पर लगे आरोपों का जवाब केवल राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया से दिया जाना चाहिए। इससे न केवल सरकार की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा भी मजबूत होता है। यह पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास की कसौटी भी है। जनता चाहती है कि आरोपों और प्रत्यारोपों की राजनीति से आगे बढ़कर तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि जांच की आवश्यकता है तो वह निष्पक्ष हो, और यदि आरोप निराधार हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए। यही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है और यही सुशासन का मूल आधार भी।

ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अग्रसर जशपुर

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में जशपुर जिले को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत जिले के चार प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए कुल 8 करोड़ 44 लाख 68 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा आवागमन के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। शासन के इस निर्णय से क्षेत्रवासियों में उत्साह और खुशी का माहौल है। राज्य शासन द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार बुलडेगा से रेचवाघाट पहुंच मार्ग (1.20 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 1 करोड़ 23 लाख 77 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा दैनिक आवागमन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। इसी प्रकार खुंटापानी से सलियामुड़ा पहुंच मार्ग (3 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 3 करोड़ 46 लाख 67 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मार्ग कई गांवों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क बनने से विद्यार्थियों को विद्यालय, मरीजों को स्वास्थ्य संस्थानों तथा किसानों को कृषि उपज के परिवहन में बेहतर सुविधा मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में सड़क संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, विद्यार्थियों और मरीजों का आवागमन सुगम होगा तथा स्थानीय व्यापार और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

पीओके चुनावी हिंसा में 37 लोगों की मौत

पाक अधिकृत कश्मीर में बदलाव की तस्वीर

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में लगातार हालात हिंसक एवं तनावपूर्ण हुए हैं। रावलकोट और मीरपुर में हिंसा के चलते संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर 37 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने पीओजेके के इन हालातों पर गंभीर चिंता जताई है। गौरतलब है कि जेएएसी पिछले करीब दो माह से पीओजेके की तथाकथित विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर आंदोलन चला रही है। संगठन का आरोप है कि ये 'शरणार्थी निर्वाचन क्षेत्र' उन मतदाताओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, जो पीओजेके के मूल निवासी नहीं है। इनमें से ज्यादातर की वैधानिक पुष्टि भी नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार इन सीटों के जरिए अपनी पसंद की सरकार चुनवा कर मर्जी का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसी मनमानी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा बिजली, सस्ता आटा और अन्य खाद्य सामग्री की कमी भी आक्रोश का कारण बनी हुई है। भारत ने इन इन चुनावों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश कहा है। जबकि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है।

पीओजेके में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक तीन चरणों में चुनाव होने हैं। चुनावों में कुल 45 सीटों में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। किंतु गुलाम जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटें मंजूर नहीं हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग जबरदस्त विरोध पर उतर आए हैं। इस विरोध के चलते पहले 46 प्रदर्षनकारी और अब मतदान के दौरान 37 लोग मारे जा चुके हैं, सैंकड़ों लोग घायल हैं। पाक आर्मी और पुलिस के इस दमन एवं नरसंहार से आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़क गया है। इस जोष और नाराजगी को दबाने के लिए पूंछ, मीरपुर एवं मुजफ्फराबाद में बड़ी संख्या में अतिरिक्त अर्ध सैनिक बल तैनात कर दिए हैं। दरअसल लोगों का गुस्सा इसलिए फूट रहा है, क्योंकि ये चुनाव अंतरराष्ट्रीय समुदाय एवं मानवाधिकार आयोग को यह दिखाने के लिए कराए जा रहे हैं कि पाकिस्तान लोकतंत्र का पैरोकार है। लेकिन यह पूरा नाटक फरेब की नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। भारत भी इस चुनाव के विरोध में है।

इस विरोध का प्रमुख कारण पीओजेके में विधानसभा की 45 निर्वाचित सीटों में से 12 सीटों का शरणार्थियों के लिए आरक्षित करना है। जेएएसी का आरोप है कि इन सीटों के कारण स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। संगठन लंबे समय से इन सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। चुनाव के ठीक पहले यह मुद्दा राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनषील बन गया है। इस मुद्दे के साथ-साथ आमजन बढ़ती महंगाई, गेंहू और आटे की उपलब्धता में कमी, बिजली की दरों में वृद्धि, बेरोजगारी तथा स्थानीय प्रषासनिक अधिकारों की मांग को भी आगे बढ़ा रहा है। दरअसल शरणार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने का मतलब, स्थानीय लोगों को जनप्रतिनिधित्व से बहिश्कृत करने का संवैधानिक उपाय पाकिस्तान ने मान लिया है। अतएव ये चुनावी फरेब पीओजेके पर अवैध कब्जे को वैध ठहराने का उपाय भर है। पाकिस्तान इस चुनाव के जरिए यह जताने का उपक्रम कर लेता है कि वह लोकतंत्र का पक्षधर होने के साथ भू-राजनीतिक शक्ति भी है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को इस चुनावी हथकंडे को राश्ट्रीय सुरक्षा नीति के परिदृष्य में इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में अंतरराश्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेष करने के साथ हस्तक्षेप की मांग करने की जरूरत है। हालांकि पीओके में हुई हिंसा को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाक पर करारा हमला बोला है। कहा है कि पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए। पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं को छुपाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए झूठी खबरों और फर्जी वीडियो का सहारा ले रहा है। जबकि पीओजेके में आर्मी और पुलिस ने बर्बर कार्यवाही की है। हम उम्मीद करते है कि विश्व समुदाय पाक के इन कृत्यों के लिए उसे जवाबदेह ठहराएगा।

इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के गलियारों से ऐसी खबर आई है, जिसने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक कूटनीति के दोहरे मानदंडों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में पाकिस्तान और चीन की एक साझा और बेहद महत्वाकांक्षी कोशिश को अमेरिका ने पूरी तरह से असफल कर दिया। इन दोनों देषों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसके आत्मघाती दस्ते 'मजीद ब्रिगेड' को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर वीटो लगा दिया है। जबकि दिलचस्प बात है कि खुद अमेरिका ने 2019 में बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अपनी घरेलू फारेन टेररिस्ट आर्गेनाइजेशन सूची में शामिल किया था। बावजूद वैश्विक मंच पर चीन और पाकिस्तान के इस साझा प्रस्ताव को अमेरिका और उसके पष्चिमी सहयोगियों द्वारा रोका जाना एक बड़ा कूटनीतिक संदेष है। यह वही चीन है, जिसने अतीत में भारत और अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों को वैश्विक प्रतिबंधित आतंकवादी सूची में डालने से जुड़े कई प्रस्तावों पर वीटो लगा दिया था। सुरक्षा परिशद् का यह घटनाक्रम संकेत देता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरहदों पर ही नहीं बल्कि बंद कमरों में भी कूटिल कूटनीति के लिए लड़ी जाती है। पीओजेके में वर्तमान नरसंहार को लेकर ब्रिटेन के 50 सांसदों ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदायों के समक्ष चिंता जताई है। भारत को पीओजेके में उभरे इस आंतरिक संकट और नरसंहार से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि धूर्त पाकिस्तान इस ओट में अपनी पुरानी और नापाक चालें चलते हुए प्रशिक्षित आतंकियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की चाल चल सकता है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ इस अराजकता और खून-खराबे की आड़ में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ कराकर जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य नगरों में हिंसा व अषांति फैलाने की दृश्टि से आत्मघाती हमले करा सकती है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इधर पीओजेके में आमजनों पर सुरक्षा बलों की बर्बरता को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उचित ठहराया है। उन्होंने अधिकारों और पहचान दिए जाने की मांग कर रहें कश्मीरियों को भारत जैसा दुश्मन करार दिया है। आसिफ के इस बयान को इस तथ्य की स्वीकार्यता माना जा रहा है कि गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग भारतीय जम्मू-कश्मीर की भूमि का हिस्सा हैं। हकीकत भी यही है। पीओजेके की परिधि में आने वाले गिलगित-बाल्टिस्तान वास्तव में भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्सा हैं। बावजूद पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं। लेकिन यहां के नागरिकों ने इस बलात कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा। यहां तभी से राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं और पाक सरकार इन लोगों पर दमन और अत्याचार का सिलसिला जारी रखे हुए है। साफ है, पाक की आजादी के साथ गिलगिट-बाल्टिस्तान का मुद्दा जुड़ा हुआ है। पाक की कुल भूमि का 40 फीसदी हिस्सा यहीं है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं, इसलिए इसे गिलगिट-बलूचिस्तान भी कहा जाता है। पाक और बलूचिस्तान के बीच संघर्श 1945, 1958, 1962-63, 1973-77 में होता रहा है। 77 में पाक द्वारा दमन के बाद करीब 2 दशक तक यहां शांति रही। लेकिन 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर अवैध कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आए, इनमें प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है।

यहां की विधानसभा को अपने बूते कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सारे फैसले एक परिषद लेती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। लिहाजा चुनाव के बावजूद भी यहां विद्रोह की आग सुलगी रहती है। यह आग उन सब इलाकों में सुलगी रहती है, जो षिया बहुल हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में षिया और अहमदिया मुस्लिमों समेत सभी धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अहमदिया मुस्लिमों के साथ तो पाक के मुस्लिम समाज और हुकूमत ने भी ज्यादती बरती है। 1947 में उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। तब से वे न केवल बेगाने हैं, बल्कि हिंदू, सिख व ईसाइयों की तरह मजहबी चरमपंथियों के निशाने पर भी रहते हैं।

इस क्षेत्र में चीन बड़ा निवेष कर रहा है। ग्वादर में एक बड़ा सा बंदरगाह बनाया है। चीन की एक और बड़ी योजना है, 'चाइना-पाकिस्तान इकोनामिक कारिडोर' इसकी लागत 3 लाख 51 हजार करोड़ है। यह गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान से गुजर रहा है। इस गलियारे के निर्माण में लगे चीनी नागरिकों की आतंकी संगठन बीएलए हत्याएं कर रहा है। चूंकि यह क्षेत्र अधिकारिक रूप से भारत का है, इसलिए भारत भी इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। पाकिस्तान रणनीतिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत बना लेने की फिराक में लगा है। चूंकि यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत के जम्मू-कश्मीर प्रांत का हिस्सा है, इसलिए यहां कोई भी बदलाव कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन होगा। अतएव इन क्षेत्रों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करना भारत की राश्ट्रीय सुरक्षा रणनीति होना चाहिए। क्योंकि भारत के पास अपनी-अपनी स्थिति को मजबूती से रखने के लिए राजनीतिक कानूनी और संवैधानिक आधार मौजूद हैं।पाकिस्तान यहां सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर इस पूरे क्षेत्र का जनसंख्यात्मक घनत्व बदलने के प्रयास में भी लगा है। इन कारणों के चलते यहां के मूल बलूचों की पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त नाराजी है और वे निर्णायक लड़ाई लड़के भारत में विलय होने की कोशिश में लगे हैं।

बढ़ते शहरीकरण के दबाव में बिगड़ा पर्यावरण संतुलन

शहर में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के दबाव के बीच पेड़ों की लगातार कटाई ने स्थानीय पर्यावरण और नागरिकों की ताजी सांसों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हर कटे हुए पेड़ के साथ गर्मी बढ़ रही है, धूल और प्रदूषण का स्तर ऊँचा हो रहा है और पक्षियों तथा छोटे जीवों के रहने-सहन के ठिकाने मिट रहे हैं, जिससे न सिर्फ़ पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य तथा जीवन-गुणवत्ता पर भी गहरा असर पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि शहर की हरियाली बचाने के लिए सख्त नीतियाँ, सामुदायिक भागीदारी और वृक्षारोपण के दीर्घकालिक समाधान अपनाए जाएँ।

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

वृक्ष प्रकृति का हरित श्रृंगार है। स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का सचेतक है, पोषक है और रक्षक भी है। प्राणवायु आक्सीजन के शुद्धिकरण का सतत् प्राकृतिक संयंत्र भी है ।इस तरह वृक्ष जीवनदाता है। वृक्ष है तो वन है, वन है तो बारिश है, बारिश है तो जल है, और जल है तो जीवन है। इस प्रकार वृक्ष है तो जीवन है। शायद यही कारण रहा होगा कि भगवान श्रीकृष्ण ने भागवत गीता में 'अश्वत्थः सर्व वृक्षाणां' कह करस्वयं को पीपल कहा है। वृक्ष को लेकर यजुर्वेद में कहा गया है-''वनानांपतेय नमः, वृक्षाणां पतेय नमः, औषधीनां नमः अर्थात वनों के पति को नमस्ते, वृक्षों के पति को नमस्ते एवं औषधियों के पति को नमस्ते। इस तरह यहां वृक्षों और औषधियों के प्रति आदर-सत्कार की भावना का समर्थन किया गया है। वृक्ष के महत्त्व को रेखांकित करते हुए 'मत्स्य पुराण' में भी कहा गया है कि -" दशकूप समावापी, दशवापी समोह्रदः/दशह्रद समः पुत्रो,दशपुत्र समोद्रुमः" यानी दस कूपके बराबर एक वापी (वाबड़ी), दस वापी के बराबर एक ह्रद (तालाब), दस ह्रद के बराबर के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। इस तरह संसारिक जीवन में वृक्ष की महत्ता और उपादेयता को रेखांकित किया गया है। ये वृक्ष मनुष्य के साथी और सहायक हैं। ये हमसे कुछ लेते नही बल्कि बहुत कुछ देते हैं। वृक्ष हमारे जीवन का हिस्सा है क्योंकि इसके अलावा हमें जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन कोई नही दे सकता है। आज जलवायु परिवर्तन सबसे बडे खतरों मे से एक है। जिसका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं और वृक्ष उन चीजों में से एक है जो हमें जलवायु संकट के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। वृक्ष वातावरण को शुद्ध रखता है जिससे हमारा जल, वायु और ध्वनि प्रदुषण से बचाव होता है और खतरनाक बीमारियों से भी हमें पेड़ बचाते हैं। वृक्ष कार्बन का भंडारण करते हैं। वृक्ष कार्बन को हवा से बहार खींचते हैं और इसे अपने जड़ों और आसपास की मिट्टी में संग्रहित करते हैं। एक अनुमान के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई वन वर्तमान में 22 बिलियन टन कार्बन भंडारण कर रहे हैं। यह 4.7 अरब कारों से कुल उत्सर्जन के बराबर है। कार्बन भंडारण से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ जितना पुराना होता है वह वातावरण से कार्बन को उतना ही बेहतर अवशोषित करता है। इसलिए जरूरी है कि हम परिपक्व वृक्षों और जंगलों को विनाश से बचाएं। यह सभी प्रभावशाली कार्बन कैप्चर समग्र कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक तापमान को कम करने में मदद करता है, बदले में बढ़ते तापमान और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रभावों को कम करता है। वृक्ष हमारे मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं। हम सभी ने यह महसूस किया होगा कि जब घने पेड़ों के बीच से हम गजरते हैं तो जंगलों के ऊपर धुंध दिखती है और ज्यादा ठंड महसूस होती है। पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से अपनी शाखाओं में पानी को खींचते है जहां अंततः इसे पेड़ की पत्तियों में छोटे छिद्रों के माध्यम से वापस हवा में छोड़ दिया जाता है। इसे वाष्पीकरण कहते है। नमी की यह रिहाई आसपास के तापमान को ठंडा करती है और बारिश के बादलों को बनाने में मदद करती है और बारिश के पानी को वापस जंगल में गिरा देते हैं। यह एक अंतहीन और महत्तवपूर्ण चक्र है। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि भूमि पर होने वाली 40 प्रतिशत वर्षा जल वाष्प के कारण होती है। जो पेड़ों द्वारा वातावरण में छोड़ी जाती है। वृक्ष प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण सभी दृष्टि से हमारे लिए आवश्यक है। पुत्र की भांति वृक्ष का संपोषण हमें करना चाहिए। वृक्षों के बारे में हमारी नयी पीढ़ी की जानकारी दिन पर दिन निरन्तर सीमित होती जा रही है। कैसी विडम्बना है कि मानव जीवन को सौन्दर्य की सुखद अनुभूति से भर देने वाली वृक्ष-सम्पदा दिनों दिन उपेक्षित होती जा रही है और अति दोहन का शिकार बनती जा रही है। हमारी संस्कृति का यही उदघोष रहा है। हमें अपनी परंपरा और वर्तमान वैज्ञानिकों और चिंतकों के इस आह्वान पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और क्रियान्वयन करना चाहिए। यह दायित्व हमारा भी है, न कि केवल शासन और प्रशासन का।

युवा आक्रोश: जिम्मेदारों की जवाबदेही और लोकतंत्र की ताकत

दिल्ली का जंतर-मंतर केवल विरोध का एक पता नहीं, बल्कि देश के युवाओं की बेचैनी, उम्मीद और टूटते भरोसे का प्रतीक बन गया था। यहाँ खड़ा हर युवा मानो अपने मन में एक ही प्रश्न दोहरा रहा था, क्या उसका भविष्य भी आश्वासनों, आंदोलनों और इंतजार के इसी जंतर-मंतर में उलझकर रह जाएगा, या उसकी मेहनत को कभी निष्पक्ष अवसर भी मिलेगा? मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा-व्यवस्था की अनियमितताओं के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन जवाबदेही, पारदर्शी व्यवस्था और सम्मानजनक रोजगार की व्यापक मांग का स्वर बन गया। घटनाक्रम के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और जंतर-मंतर का आंदोलन भी अपने इस चरण में शांतिपूर्वक पूर्ण हुआ। अब देश की निगाहें परीक्षा-तंत्र में अपेक्षित सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर टिक गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सकारात्मक संदेश भी दिया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संवाद, जनभागीदारी और जवाबदेही की प्रक्रिया आज भी प्रभावी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने भी हाल ही में नई पीढ़ी के प्रश्नों को सुनने और संवाद के महत्व पर बल दिया। अनशन समाप्त करते हुए सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

कागज़ पर लाभांश, ज़मीन पर दबाव

भारत की युवा आबादी को लंबे समय से 'जनसांख्यिकीय लाभांश' कहा जाता रहा है। लेकिन आबादी का युवा होना अपने-आप आर्थिक शक्ति नहीं बनता। उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भरोसेमंद परीक्षाएँ, उपयोगी कौशल और पर्याप्त रोजगार चाहिए। इनमें से किसी एक कड़ी के कमजोर पड़ते ही लाभांश बोझ में बदलने लगता है। प्रतिस्पर्धा का पैमाना भयावह है। मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में बीस लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठते हैं, जबकि सरकारी मेडिकल सीटें उसका बहुत छोटा हिस्सा हैं। विश्वविद्यालयों और सरकारी भर्तियों में भी लाखों उम्मीदवार कुछ हजार अवसरों के लिए वर्षों तैयारी करते हैं। कठिन प्रतिस्पर्धा किसी भी समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही प्रश्नचिह्न लग जाए, तब मेहनत का पूरा अर्थ बदल जाता है।

एक पेपर लीक केवल प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग नहीं करता। वह अभ्यर्थी के समय, परिवार की जमा-पूंजी, माता-पिता की उम्मीद और व्यवस्था पर उसके विश्वास को भी चोट पहुँचाता है। परीक्षा रद्द होने, परिणाम अटकने अथवा भर्ती अदालतों में उलझने की कीमत कैलेंडर के कुछ महीनों से नहीं मापी जा सकती; अनेक युवाओं के लिए यही उनके जीवन के सबसे निर्णायक वर्ष होते हैं।

डिग्री बढ़ी, अवसर क्यों नहीं?

रोजगार के आँकड़ों की अलग-अलग व्याख्याएँ हो सकती हैं, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि शिक्षित युवाओं के लिए उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार का संकट गंभीर है। आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 2025 में 9.9 प्रतिशत रही। वहीं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान की भारत रोजगार रिपोर्ट ने बेरोजगार आबादी में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी तथा शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ते असंतुलन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यही विरोधाभास सबसे अधिक पीड़ादायक है। परिवार अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर बच्चों को पढ़ाते हैं, युवा डिग्रियाँ और प्रमाणपत्र जुटाते हैं, फिर भी उन्हें या तो लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता या ऐसा काम मिलता है जिसका उनकी शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता। यह केवल बेरोजगारी नहीं, बल्कि प्रतिभा का अल्प-उपयोग भी है।

विदेश जाने वाले हर छात्र को 'ब्रेन ड्रेन' कहना उचित नहीं। वैश्विक शिक्षा और अनुभव भी देश की शक्ति बन सकते हैं। चिंता तब है, जब युवा अवसरों की तलाश में नहीं, बल्कि व्यवस्था से भरोसा उठ जाने के कारण देश छोड़ने का निर्णय लेने लगें। प्रतिभा को रोकने का रास्ता भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि बेहतर विश्वविद्यालय, मजबूत शोध, निष्पक्ष चयन और योग्यतानुकूल रोजगार है।

अब सुधारों की परीक्षा

सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कानून बनाया है, लेकिन कानून की वास्तविक परीक्षा उसकी धाराओं में नहीं, उसके प्रभावी क्रियान्वयन में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और आंदोलन का शांतिपूर्ण समापन इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव अवश्य है, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि घोषित सुधार समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू हों। अपराधियों की त्वरित जांच, समयबद्ध मुकदमे और परीक्षा एजेंसियों की संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। हर बड़ी भर्ती के लिए आवेदन से नियुक्ति तक बाध्यकारी कैलेंडर बनाया जाए तथा अनावश्यक विलंब पर स्पष्ट जवाबदेही तय हो।

साथ ही शिक्षा को डिग्री-केंद्रित ढांचे से आगे ले जाकर उद्योग, अप्रेंटिसशिप और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा। युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला मानकर उद्यमिता का उपदेश देना पर्याप्त नहीं है; उन्हें आसान ऋण, मार्गदर्शन, बाजार तक पहुँच और असफलता के बाद दोबारा खड़े होने का अवसर भी देना होगा। मानसिक स्वास्थ्य सहायता को भी कोचिंग नगरों, विश्वविद्यालयों और भर्ती संस्थानों की व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

जंतर-मंतर से उठी युवाओं की आवाज़ किसी विशेष आग्रह की नहीं, बल्कि निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद व्यवस्था की थी। आंदोलन का यह चरण अब पूरा हो चुका है, लेकिन उसने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही और युवाओं के विश्वास को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। अब अपेक्षा केवल इतनी है कि संवाद से आगे बढ़कर सुधार जमीन पर भी दिखाई दें। युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। यह पूंजी केवल संख्या से नहीं, विश्वास से बनती है। यदि व्यवस्था उस विश्वास की रक्षा कर सके, समय पर संवाद स्थापित करे और आवश्यक सुधारों को धरातल पर उतारे, तो यही विश्वास भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। विकसित भारत का मार्ग केवल आर्थिक विकास दर से नहीं, बल्कि उस भरोसे से तैयार होगा, जिसके साथ देश का हर युवा यह कह सके कि उसकी मेहनत का सम्मान अवश्य होगा।

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं **त्वरित, पारदर्शी और आसान**

520
शासकीय सेवाएं

घर बैठे, एक क्लिक में

नागरिकों के लिए सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं

R.O. No. : 13930/ 2

95.9%
आवेदनों का निराकरण

- **38 लाख+** आवेदन
- **16,700+** सेवा केंद्र
- **36 विभाग** एक मंच पर

प्रमुख सेवाएं

- ✓ **जाति प्रमाण** पत्र
- ✓ **आय प्रमाण** पत्र
- ✓ **निवास प्रमाण** पत्र
- ✓ **विवाह प्रमाण** पत्र
- ✓ **राशन कार्ड** सेवाएं
- ✓ **पेंशन** योजनाएं
- ✓ नाम **परिवर्तन सेवा**
- ✓ व्यापार **लाइसेंस**

अधिक जानकारी हेतु ◂ स्कैन करें

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)